

लोकसभा अध्यक्ष अपने “डिस्केशनरी फण्ड” का बहुत “सही” उपयोग कर रहे हैं!

अविश्वास प्रस्ताव को बेअसर करने के लिए, 60 देशों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजे जाएंगे लोकसभा सचिवालय की ओर से, भारत की संसदीय व्यवस्था की सुंदर कहानी पेश करने के लिए

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 फरवरी। क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला अपने व्यक्तिगत पीआर के लिए राष्ट्रीय खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं? लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 9 मार्च को सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। जब सदन एक ब्रेक के बाद फिर से चलेगा, उसी दिन प्रस्ताव लाया जाएगा। सांसदों और अधिकारियों के बीच गुपचुप चर्चा हो रही है कि स्पीकर ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी तादाद में नेताओं व सांसदों को 60 देशों में भेजने का कार्यक्रम बनाया है।

विभिन्न समूह बनाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद के दौर में किए गए प्रयासों की तरह ही विभिन्न देशों के साथ संपर्क बनाने का

- इस मकसद से 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मित्रता ग्रुप बनाए गए हैं।
- विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं, जैसे पी. चिदम्बरम, शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, टी.आर. बालू, के.सी. वेणुगोपाल, अखिलेश, ओवैसी, अभिषेक बनर्जी, सुप्रिया सूले, अनुराग ठाकुर आदि को संसदीय मित्रता ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है।
- श्री लंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, अमेरिका, रूस, यूरोपीयन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान व यू.ए.ई., को भेजे जाने वाले ग्रुप्स गठित हो चुके हैं तथा साथ ही इस सूची में सम्मिलित नाम साठ की संख्या पार कर जाएंगे।
- ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्र.मंत्री ने भी कई ग्रुप्स बनाये थे, जिन्हें विदेश भेजा गया था तथा इन ग्रुप्स की यात्रा का काफी व्यापक व सकारात्मक असर हुआ था। ओम बिड़ला चाह रहे हैं कि संसदीय ग्रुप की वर्तमान विदेश यात्राओं से भी ऐसा ही नतीजा निकलेगा।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोकसभाध्यक्ष के “डिस्केशनरी फण्ड” का कोई ऑडिट नहीं होता, राष्ट्रपति के “डिस्केशनरी फण्ड” की भांति। अतः संसदीय मंत्री ग्रुप्स की विदेश यात्राएं निर्विज्ज रूप से पूर्ण होगी शीघ्र ही।

कार्य करेंगे, ताकि भारत के दृष्टिकोण को सामने लाया जा सके। कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ चल रही आलोचनाओं को दबाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जल्दी ही अलवर तक भी आएगी रैपिड रेल

दिल्ली से मेरठ तक का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 फरवरी। भारत का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस), जो दिल्ली से 82 किमी की दूर स्थित मेरठ को जोड़ेगा, अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को इस लाइन के अग्रे 26 किमी खंड का उद्घाटन किया। ट्रेनों का परिचालन 10 मिनट के अंतराल पर होगा, जो दिल्ली के समय काले खान से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक की यात्रा 55 मिनट में पूरी करेगी।

साथ ही, मेरठ मेट्रो का 23 किमी का खंड भी लॉन्च किया गया है- जो आरआरटीएस ट्रेकों और सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग करेगा। अधिकारियों ने कहा, इसे भारत की सबसे तेज मेट्रो रेल प्रणाली के रूप में पेश किया गया है, जिसकी अधिकतम संचालन गति 120 किमी/घंटा होगी,

- प्रधानमंत्री ने रविवार को पहले रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विधिवत् उद्घाटन किया।
- इसी बीच केन्द्रीय शहरी मामलात मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली-अलवर और दिल्ली-करनाल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की बात कही।
- पहले रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के शुभारंभ के साथ ही मेरठ मेट्रो का 23 किलोमीटर लंबा रेल खंड भी शुरू किया गया। अब देश का मेट्रो रेल नैटवर्क 1100 किलोमीटर तक बढ़ चुका है।

और पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी होगी। यात्री चार स्टेशनों पर आरआरटीएस और मेट्रो इंटरचेंज कर सकते हैं: मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगम पुल और मोदीपुरम। अधिकारियों ने कहा, अब मेरठ के जुड़ने से, देश का मेट्रो नेटवर्क 24 शहरों में 1,100 किमी तक बढ़ चुका है। 180 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड और 160 किमी/घंटा की संचालन स्पीड के साथ, दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस भारत का पहला परिवहन प्रोजेक्ट है, जो क्लस्टर-आधारित शहरी विकास की अवधारणा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन पुनः बिखराव की ओर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 फरवरी। आगामी राज्य सभा और महाराष्ट्र विधान परिषद

- इस बार मसला है, राज्यसभा की रिक्त हुई सीटों का। महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें खाली होंगी, इनमें से सिर्फ एक विपक्ष को मिलेगी और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तीनों घटक, शिव सेना, कांग्रेस व एनसीपी की इस एक सीट पर नजर है।

चुनावों ने विपक्षी खेमें में हलचल मचा दी है और महा विकास अघाड़ी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश

रांची, 23 फरवरी। रांची से एक मरीज को इलाज के लिए दिल्ली लेकर जा रही एक एयर एंबुलेंस सोमवार रात चतरा में क्रैश हो गई। इस विमान पर मरीज समेत कुल सात लोग सवार थे, जिनमें सभी की मौत हो गई।

बताया जाता है कि आग से गंभीर रूप से झुलसे, लातेहार के चंदवा निवासी मरीज संजय कुमार को शाम 7:11 बजे रांची के देवकमल अस्पताल से दिल्ली ले जाया जा रहा था। रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के, बीच क्राफ्ट सी 90 एयर एंबुलेंस में

- चतरा जिले के पास सिमरिया में हुए हादसे में विमान में सवार मरीज सहित सभी सात लोगों की मौत हो गई।

मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी व एक अन्य स्वजन ध्रुव कुमार के अलावा एंबुलेंस टीम के कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन स्वराज दीप सिंह, डॉ. विकास कुमार गुप्ता और पैरा मेडिकल स्टाफ सचिन कुमार गुप्ता सवार थे।

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि शाम 7.34 बजे एयर टैफिक कंट्रोल (एटीसी) से विमान का संपर्क अचानक टूट गया। संपर्क टूटते ही तत्काल हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हरदीप पुरी के बारे में नया विवाद खड़ा हुआ, एफ्टीन से संबंधों के बारे में

सोशल एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने पुरी का एफ्टीन को लिखा एक पत्र ट्विटर पर डाला

- इस पत्र के अनुसार, पुरी ने एफ्टीन के एक नजदीकी मित्र को 2013 में पत्र लिखकर धन्यवाद दिया, पुरी की पुत्री हिमानी पुरी की व्यवसायिक कंपनी में 2,400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। यह उस समय की बात है जब 2013 में, हरदीप पुरी भारत की “फॉरेन सर्विस” की पोस्ट, यू.एन. में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद से रिटायर हुए ही थे तथा उन पर आरोप था कि वे कंपनी से सम्बद्ध बिज़नेस के लिए “लॉबिंग” कर रहे थे।
- इस प्रसंग का एक रोचक पहलू यह भी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की बड़ी सुस्त सी प्रतिक्रिया आई। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस इस प्रकरण से जुड़े कागज़ातों की सच्चाई व विश्वसनीयता का गहराई से अध्ययन कर रही है तथा निष्कर्ष पर पहुँचकर ही अपनी प्रतिक्रिया देगी।

कुछ वर्ग इस मामले में स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। विवाद ने तब जोर पकड़ा जब सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इसे पुरी का निजी पत्र बताया। अपनी पोस्ट में शुक्ला ने आरोप लगाया कि राजनयिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद कुछ वर्ग इस मामले में स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। विवाद ने तब जोर पकड़ा जब सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इसे पुरी का निजी पत्र बताया। अपनी पोस्ट में शुक्ला ने आरोप लगाया कि राजनयिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद

पुरी न्यूयॉर्क में अपनी बेटी के कारोबारी हितों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, इस दस्तावेज की प्रामाणिकता और पत्राचार के संदर्भ की अब तक आधिकारिक खोजों से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में कांग्रेस से पलायन रोकना बड़ी चुनौती है प्रियंका के लिए

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेन बोरा ने भाजपा में शामिल होकर प्रियंका के लिए चुनौती बढ़ा दी है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 फरवरी। असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सંभालते हुए, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने राज्य का दो दिवसीय दौरा पूरा किया। यह दौरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही दिन बाद हुआ। करीब 30 वर्षों तक कांग्रेस में रहे बोरा, जो जुलाई 2021 से मई 2025 तक असम इकाई के अध्यक्ष रहे, ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ दी। सूत्रों के अनुसार, जब से गौरव गोगोई उनकी जगह राज्य पार्टी अध्यक्ष बने हैं, तब से वे असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि नए प्रदेश अध्यक्ष धुबरी के सांसद रकीबुल हुसैन को अधिक महत्व दे रहे हैं।

- प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं और उन पर सही प्रत्याशियों के चयन की भी जिम्मेवारी है, साथ ही गठबंधन के लिए सही सहयोगियों की तलाश भी उन्हें करनी है। इसके लिए वे फूक-फूक कर कदम उठा रही हैं।
- अपने हालिया असम दौरे में उन्होंने राज्य के सभी कांग्रेसी विधायकों, सांसदों व जिला तथा ब्लॉक अध्यक्षों से भी मुलाकात की।
- सूत्रों का कहना है कि राज्य में भाजपा का संगठन काफी मजबूत है, कांग्रेस भले ही बड़ी जीत प्राप्त न कर पाए, पर, अगर उसने स्थिति पहले से बेहतर कर ली तो भी इससे प्रियंका की सफलता माना जाएगा।

शुक्रवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद, एनडीटीवी से बातचीत में बोरा ने कहा कि वे रविवार को भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 8 मार्च

तक कांग्रेस के कई अन्य नेता भी भाजपा में जा सकते हैं। प्रियंका गांधी के लिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता इस संभावित पलायन को रोकना और चुनाव से पहले पार्टी को

एकजुट रखना होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्यों में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, डी के शिवकुमार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद इमरान मसूदर शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान, गांधी ने असम के 21 विधायकों, तीन सांसदों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की। उम्मीदवारों के चयन के अलावा, गांधी और कांग्रेस के सामने एक और बड़ी चुनौती भाजपा का सामना करने के लिए सही सहयोगियों का चयन करना होगा। ज्ञातव्य है कि भाजपा लगातार दो कार्यकाल से सत्ता में है और चुनाव से पहले उसे बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 2021 में, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य की 126 में से 75 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोड़ को केवल 50 सीटें मिली थीं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अनिल अंबानी पर बैंक की कार्यवाही से रोक हटी

मुंबई, 23 फरवरी। उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से सोमवार झटका लगा। अदालत ने वह स्टे आदेश हटा दिया, जिसने बैंकों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रखा था। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज की उस अंतरिम राहत को

- बॉम्बे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच का स्टे हटाया।

रद्द कर दिया, जिसमें तीन बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक तथा ऑडिटर बीडीओ इंडिया एलएलपी को कार्रवाई से रोका गया था। यह पूरा मामला आरबीआई की 2024 मास्टर डायरेक्शंस ऑन फ्रॉड क्लासिफिकेशन से जुड़ा है। सिंगल जज ने दिसंबर 2025 में अनिल अंबानी को राहत देते हुए कहा था कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करने वाले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)